फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 74 संख्याः 37 प्रभात जयपुर, गुरुवार 7 सितम्बर, 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 3.50 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

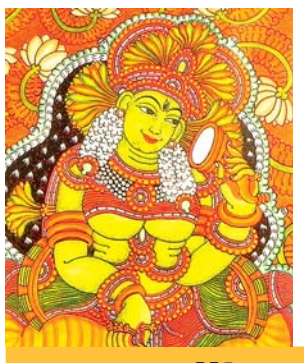

Retelling The Story of Krishna

Devdutt Pattanaik seamlessly weaves the story from Krishna's descent to the butter-smeared world of happy women to his ascent from the blood-soaked world of angry men.

Jai Shree Krishna!

Life Changing Lessons to Learn from Lord Krishna

डायनासॉर के समय ही विलुप्त मान लिए गए सीलोकैन्थ (एक प्रकार की मछली) का गर्भकाल सबसे लंबा होता है और ये सिर के बल शिकार करती हैं। वैस्ट इण्डियन ओशन सीलोकैन्थ या अफ्रीकन सीलोकैन्थ को कोमोरोस आइलैण्ड्स पर ''गॉमवैसा'' कहकर बुलाते हैं। वैज्ञानिक सोचते थे कि, सभी सीलोकैन्थ साढ़े छः करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो गए थे- फिर सन् 1938 में अचानक ही, दक्षिण अफ्रीका के तट के पास इन्हें देखा गया। सीलोकैन्थ सबसे पहले 40 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, लेकिन इनका जीवाश्म रिकॉर्ड उसी समय तक मिला जब डायनासॉर विलुप्त हुए। तथापि, इनकी अप्रत्याशित वापसी का अर्थ है कि, ये वही प्रजाति हैं जिन्हें लैज़रस कहते हैं। ये प्राचीन मछलियाँ दिन के समय गुफाओं में छुपकर रहती थीं और भोजन के लिए रात को बाहर निकलती थीं। ये साढ़े छः फीट तक लंबी और 90 किलो तक वजनी हो सकती हैं और बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। प्रारंभिक अध्ययनों से लगा था कि, इनका अधिकतम जीवनकाल 20 वर्ष होता है। लेकिन, 2021 में शोधकर्ताओं ने अधिक विकसित तकनीकों का उपयोग करके पता लगाया कि, इनकी उम्र सौ वर्ष तक हो सकती है। अध्ययन में यह भी सामने आया कि, इनमें सैक्शुअल परिपक्वता बहुत देर से आती है। नर सीलोकैन्थ 40 तथा मादा 58 वर्ष की होने पर प्रजनन करती हैं। इनका गर्भकाल 5 वर्ष का होता है। कंकाल की विशिष्ट संरचना के कारण ये सिर के बल खड़े होकर शिकार कर सकती हैं। वैस्ट इण्डियन ओशन सीलोकैन्थ की खोज के लगभग 60 वर्षों के बाद वैज्ञानिकों को इण्डोनेशिया में सीलोकैन्थ की एक और प्रजाति मिली, जहाँ इसे ''राजा लाउट'' (समुद्र का राजा) कहते हैं।

अशोक गहलोत समन्वय समिति में शांति धारीवाल को सदस्य बनवाने में सफल हुए

गहलोत ने अपने पुत्र वैभव गहलोत को भी कैम्पेन कमेटी का सदस्य बनवाया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। राज्य में चूँकि चुनाव नज़दीक ही हैं, इसलिये राज्य के विधानसभा चुनावों के लिये कांग्रेस आलाकमान ने कई कमेटियाँ गठित कर दी हैं।

रंधावा की अध्यक्षता में, 8 सदस्यों की एक कोर कमेटी गठित की गई है, जिसमें शामिल हैं-अशोक गहलोत, डोटासरा, जितेन्द्र सिंह, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, महेन्द्र जीत मालवीय, सी.पी. जोशी, मोहन प्रकाश तथा गोविन्द राम मेघवाल।

दिलचस्प बात यह है कि अशोक गहलोत ने अपने विश्वस्त शांति धारीवाल को समन्वय समिति का सदस्य बनवाने में सफलता हासिल कर ली है। और वे अपने पुत्र वैभव गहलोत को वे प्रचार समिति में ले आये हैं, जिसके अध्यक्ष गहलोत सरकार के मंत्री गोविन्द राम मेघवाल बनाये गये हैं। चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विधानसभा के स्पीकर सी.पी. जोशी बनाये गये हैं, जबकि रणनीतिक समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी होंगे।

- कांग्रेस हाई कमान ने दर्जन भर कमेटियाँ बनाईं राजस्थान विधानसभा चुनाव के बारे में।
- इतनी ज्यादा कमेटियाँ बना दी गई हैं कि, एक-दूसरे के कार्य क्षेत्र को ''ओवरलैप'' कर रही हैं। इस ''कन्फ्यूज़न'' में कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट कार्य शैली नज़र नहीं आ रही है।
- वरिष्ठ नेताओं ने कहा, जमीनी हकीकत यह है कि, चुनावों में कांग्रेस की स्थिति काफी डांवाडोल है।
- वरिष्ठ नेताओं का यह भी मानना है कि, अशोक गहलोत के कामकाज और कार्यशैली के बारे में काफी आक्रोश है जनता में।

इन कमेटियों में बड़ी संख्या में मंत्रियों एवं वरिष्ठ नेताओं को समायोजित किये जाने की कोशिश के अन्तर्गत, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरी कांग्रेस को ही इन कमेटियों में समायोजित कर दिया गया है।

अशोक गहलोत ने इनमें से कुछ कमेटियों में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की है लेकिन इतनी ज्यादा कमेटियां बना दी गई है जो एक दूसरे क कार्य क्षेत्र में ओवरलैप कर रही है। इससे कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली के बारे में भारी भ्रम पैदा हो गया है इसलिए इतनी कमेटियों का निर्माण निरर्थक सा हो गया है।

ऐसी आशा की जा रही है कि आगामी चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय कोर कमेटी ही लेगीं, हालांकि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि जमीनी हकीकत यह है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनावों में पार्टी की स्थिति काफी डांवाडोल है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत और उनकी सरकार के काम-काज को लेकर हर तरफ भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है।

'संसद के विशेष सत्र का एजेंडा गोपनीय क्यों है?'

सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर पूछा

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। संसद का पाँच दिवस का विशेष सत्र 18 सितम्बर को शुरु होने जा रहा है किन्तु संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा ''एक्स'' (पूर्वनाम ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से दी गई इस सूचना को छः दिन बाद भी विपक्ष को सत्र के एजेंडा के मामले में पूरी तरह अंधेरे में रखा गया है। इस पृष्ठभूमि में, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे अपने पत्र में नौ मुद्दों की सूची दी है, जिन पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता है।

- सोनिया ने पत्र में लिखा कि, आमतौर पर संसद सत्र के पहले बिज़नैस एडवायज़री कमेटी या सर्वदलीय बैठक में मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया।
- सोनिया गांधी ने पत्र में बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर, किसानों की मांगों, चीन सहित लगभग 9 मुद्दे चिन्हित किए हैं, जिन पर विपक्ष विशेष सत्र में चर्चा करना चाहता है।
- सूत्रों का कहना है कि, अगर सरकार इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाएगी तो संसद का विशेष सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है।

विशेष सत्र से संबंधित एजेंडा को गुप्त बनाये रखने का सरकार का यह कदम सर्वथा अभूतपूर्व है। सामान्यतः संसद सूत्रों के एजेंडा पर या तो लोकसभा की बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग में चर्चा होती है या फिर लोकसभा अध्यक्ष इस संबंध में एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं। वर्तमान स्थिति में, यह विशेष सत्र ''कौन बनेगा करोड़पति'' के शो का रूप ले चुका प्रतीत हो रहा है। क्या यह विशेष सत्र समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) पारित करने के लिये आहूत किया गया है? महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिये बुलाया गया है? देश का नाम ''इंडिया'' से बदल कर ''भारत'' कर देने का कानून बनाने के लिये बुलाया गया है? जस्टिस जी. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर चर्चा के लिये बुलाया गया है? या चन्द्रयान मिशन जी-20 सम्मेलन की सफलता का जश्न मनाने के लिये बुलाया गया है?

जहाँ विपक्षी नेता सत्र के एजेंडा को लेकर पूरी तरह अँधेरे में है, वहीं भाजपा के सांसदों एवं मंत्रियों को भी संभवतः एजेंडा की कोई खास जानकारी नहीं है।

इन अनिश्चितताओं तथा अटकलों-अनुमानों के चलते, सोनिया गांधी ने उन मुद्दों को चिन्हित करने की पहल की है, जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है। ये मुद्दे हैं- बढ़ती जा रही महँगाई, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की किसानों की माँग, मणिपुर में जारी साम्प्रदायिक हिंसा, चीन के साथ सीमा संबंधी मुद्दे, जातिगत सर्वे की माँग, केन्द्र-राज्य विवादों के मुद्दे तथा

(शेष पृष्ठ 4 पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है?
ऑटोमेटिक कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
कॉकलियर इम्पलांट, ऑटिजम
डिले स्पीच, हकलाना, तुतलाना
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
सम्पर्क- 94602 07080

इंडिया बनाम भारत मसले पर शब्दों का घमासान जारी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। एक ओर जहाँ मोदी सरकार ''इंडिया'' नाम को निरस्त करने की अपनी प्रतिबद्धता जताने में एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है, वहीं आज कांग्रेस नेता शशि थरुर ने इंडिया-भारत विवाद पर चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन अपने आपको ''एलायंस फॉर बैटरमैंट, हार्मनी एंड रिस्पॉंसिबल एडवांसमैंट फॉर टूमॉरो (भारत)'' रख लेगा तो शायद सत्तारूढ़ पार्टी नाम बदलने का यह ऊटपटांग खेल बंद कर दे

- आज इस विवाद में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि, अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया की जगह भारत नाम रख ले तो नाम बदलने का तमाशा शायद बंद हो जाएगा।

थरूर की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी-

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड के चारों सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष व तीन सदस्यों के खिलाफ मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ने दो एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को सोमवार तक के लिये किसी प्रकार की उत्पीड़क (कोअर्सिव) कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि इनके खिलाफ मणिपुर में विभिन्न अपराधों को लेकर दो एफ.आई.आर. दर्ज हुई थीं, जिनमें दो समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने का अपराध भी शामिल है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं मनोज मिश्रा से मिलकर बनी बैंच ने एडिटर्स गिल्ड द्वारा दायर की गई याचिका पर राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है तथा इस प्रकरण की सुनवाई के लिए 11 सितम्बर की तारीख दे दी है।

इससे पूर्व, शीर्ष अदालत याचिका की सुनवाई आज ही करने के लिये

- चीफ जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बैंच ने एडिटर्स गिल्ड की याचिका पर यह आदेश दिया तथा मणिपुर सरकार से जवाब मांगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 सितम्बर की तारीख तय की है।
- 4 सितम्बर को मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एडिटर्स गिल्ड के चार सदस्यों के खिलाफ, राज्य में हिंसा और तनाव भड़काने का आरोप लगाते हुए एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी।
- इन पर दूसरी एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई, जिसमें मानहानि का आरोप भी लगाया गया है।

सहमत हो गई थी।

4 सितम्बर को, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ने कहा था कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं तीन सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर केस दायर कर दिया है। इन चारों लोगों पर राज्य में ''तनाव भड़काने'' की कोशिश का आरोप लगाया है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

गणेश चतुर्थी के दिन नए भवन में होगा संसद सत्र

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। सूत्रों ने कहा है कि संसद का विशेष सत्र पुराने तथा नये-दोनों ही भवनों में होगा।

उन्होंने कहा कि सत्र 18 सितम्बर को पुराने भवन में शुरू होगा तथा 19 सितम्बर को, गणेश चतुर्थी के अवसर पर नये भवन में शिफ्ट हो जायेगा।

- सूत्रों ने बताया कि, संसद का विशेष सत्र 18 सितम्बर को पुराने भवन में शुरू होगा तथा अगले दिन 19 सितम्बर को बैठक नए भवन में आयोजित की जाएगी।

संसद के विशेष सत्र को लेकर राजनैतिक दल किंकर्तव्यविमूढ़ स्थिति में हैं क्योंकि सरकार ने पांच दिन के इस सत्र के लिये कोई एजेंडा उपलब्ध नहीं कराया है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया

(शेष पृष्ठ 4 पर)

'उदयनिधि की सनातन धर्म टिप्पणी का सख्ती से जवाब दिया जाए'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। एक तरफ जहाँ सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर विवाद थम नहीं रहा है, वहीं अब इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी उछाल रहे हैं जिनका कहना है कि उनकी टिप्पणियों का ''उचित जवाब'' जरूरी है।

यह प्रधानमंत्री की ओर से पहला और स्पष्ट संदेश है कि पूरी भाजपा द्वारा उछाले गए इस मुद्दे का उपयोग पहले पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव और बाद में आम चुनाव के दौरान पाटी के हिन्दुत्व प्रचार के लिए किया जाएगा।

क्या द्रमुक को डर या चिंता है कि उसने खुद पर ही गोल कर दिया? कदापि नहीं, इसके विपरीत द्रमुक नेता भाजपा नेताओं को चुनौती दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर खुली बहस के लिए और उदयनिधि स्वयं कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं अपने वक्तव्य को दोहराने का। उन्होंने कहा है कि वे इसे बार-बार दोहराएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो गलत है।

तमिलनाडु के राजनैतिक विश्लेषक जैसे सुमंत सी. रमण और अन्य का कहना है कि इस विवाद से द्रमुक को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आगे फायदा हो सकता है और दक्षिणपंथियों का मुकाबला कर उदयनिधि भी अपना कद बढ़ा सकते है।

जैसा कि अन्य नेताओं ने भी समझाया है, तमिलनाडु में सनातन धर्म का उल्लेख परम्परागत जाति व्यवस्था के संदर्भ में होता है जिसके खिलाफ द्रमुक लड़ रही है। उदयनिधि को तमिलनाडु से कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम और कर्नाटक से प्रियांक खड़गे का समर्थन मिला है। इससे जाहिर होता है कि दोनों को विश्वास है कि उनके क्षेत्रों में इस मसले से चुनावी नुकसान नहीं होगा।

कर्नाटक के एक राजनैतिक विश्लेषक ने याद किया कि कैसे कांग्रेस द्वारा बजरंग दल का प्रतिबंधित करने का अपना इरादा प्रकट करने के बाद वह जीती और इस बड़ा मुद्दा बनाने के प्रयास में भाजपा असफल रही। कांग्रेस को इससे अल्पसंख्यकों के वोट मजबूती से मिले और इससे जनता दल (एस.) को हार का सामना करना पड़ा।

एक विश्लेषक के अनुसार उदयनिधि के खिलाफ भाजपा का मजबूत प्रचार अगड़ी जाति के हिन्दुओं को भाजपा के पक्ष में लामबंद कर सकता है लेकिन साथ ही वह भाजपा के दलित एवं ओ.बी.सी. वोटों को काट सकता है और अगर वे इसी तरह उदयनिधि स्टालिन पर हमला बोलते रहे तो दलितों व पिछड़ों को यह पसंद नहीं आएगा क्योंकि उदयनिधि सनातन धर्म पर तीव्र प्रतिक्रिया से जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं।

उधर बिहार में इंडिया के भागीदार जनता दल (यू.) और राजद मज़बूती से जातीय जनगणना की मांग कर रहे है जिससे भाजपा चिंतित है। अब

- मोदी की इस टिप्पणी से साफ ज़ाहिर है कि, भाजपा इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। पहले तो चार राज्यों के विधानसभा चुनावों और फिर लोकसभा चुनाव में हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जोर-शोर से यह मुद्दा उछाला जाएगा।
- इस मसले पर भाजपा के तीखे तेवरों से ना तो डी.एम.के. और ना ही उदयनिधि भयभीत हैं। उदयनिधि तो कोई मौका नहीं छोड़ रहे अपनी बात दोहराने का।
- राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि, तमिलनाडू में डी.एम.के. को इस विवाद से फायदा ही होगा, क्योंकि वहां सनातन धर्म का मतलब जाति व्यवस्था से है।
- दक्षिण पंथी ताकतों को सीधी चुनौती देकर उदयनिधि अपना राजनैतिक दबदबा बढ़ा रहे हैं।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

एन.डी.ए. ने 11 प्रवक्ताओं का पैनल बनाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 सितम्बर। विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा मीडिया एवं कम्यूनिकेशन के लिये एक पैनल बनाये जाने के प्रत्युत्तर के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नैशनल डैमोक्रेटिक अलायंस (एन.डी.ए.) ने भी एन.डी.ए. के प्रवक्ताओं का एक पैनल बनाया है ताकि इसके पार्टनर वर्तमान मुद्दों पर एन.डी.ए. के सोच से अवगत रह सकें।

भाजपा के कम्यूनिकेशन इंचार्ज

- पैनल के प्रमुख, भाजपा के अनिल बलूनी हैं। इसमें एन.डी.ए. के घटक दलों के प्रवक्ता भी शामिल किए गए हैं। यह पैनल इंडिया गठबंधन के जवाब में बनाया गया है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)